

भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और प्रवाह: 2016-17 से 2018-19*

2018-19 के दौरान अर्थव्यवस्था के समग्र वित्तीय संसाधन शेष में कमी आई क्योंकि गैर-वित्तीय निगमों के निवल उधार में वृद्धि हुई और हाउसहोल्ड्स की बचत में कमी आई। अन्य निक्षेपागार निगमों के तुलन पत्र संकुचित हुए, क्योंकि हाउसहोल्ड्स जमाराशियों के बदले में अन्य प्रतिस्पर्धी वित्तीय लिखतों को पसंद करने लगे। सामान्य सरकार और सरकारी गैर-वित्तीय निगमों की वित्तीय निवल मालियत अत्यधिक ऋणात्मक होती गई। शेष विश्व से उधार लेने और देने के मामले में भारत निवल उधारकर्ता बना रहा।

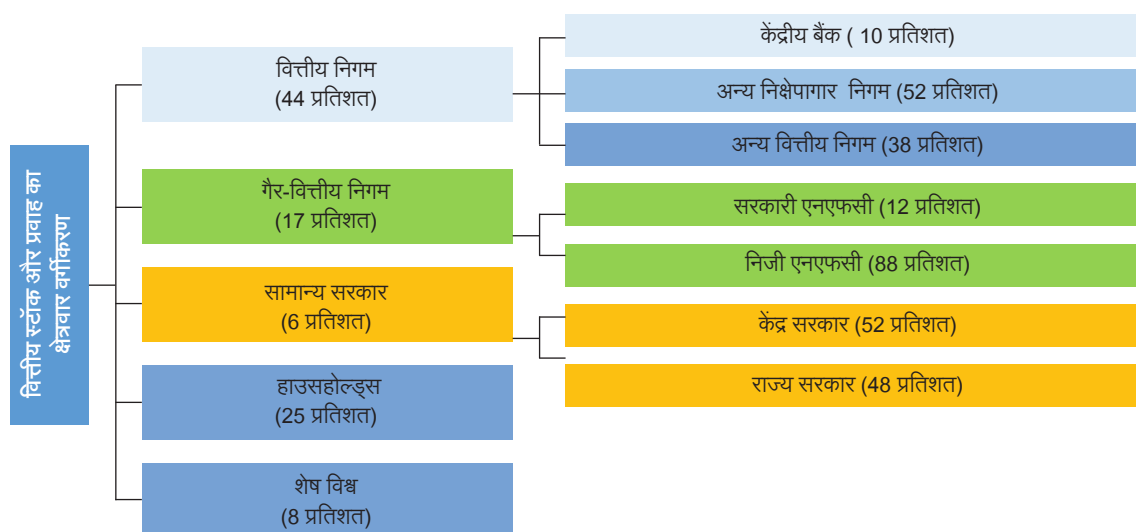
परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय स्टॉक और प्रवाह (एफएसएफ) खाता 'किससे-किसको' (एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू)

आधार पर वित्तीय लिखतों के माध्यम से क्षेत्र-वार बकाया स्थिति और लेनदेन प्रस्तुत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) 1964¹ से भारतीय अर्थव्यवस्था के धन प्रवाह (एफओएफ) खातों का संकलन और प्रकाशन कर रहा है। एफएसएफ खाता संपदा और वित्तीय क्षेत्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव तथा अर्थव्यवस्था में वित्तीय विकास के स्तर का पता लगाता है। यह वित्तीय निधियों के स्रोतों और उपयोगों तथा क्षेत्रवार वित्तीय शेष के संचलनों के संबंध में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।

एफएसएफ खाता संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय खाता 2008 (एसएनए 2008) के अनुरूप पांच संस्थागत क्षेत्रों को शामिल करता है: (i) वित्तीय निगम (एफसी); (ii) गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी), सरकारी और निजी; (iii) सामान्य सरकार (जीजी); (iv) हाउसहोल्ड्स और हाउसहोल्ड्स की सेवा में लगे गैर-लाभकारी संस्थाएं (एनपीआईएसएच)²; और (v) शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) (प्रदर्शनी 1)।

प्रदर्शनी 1: वित्तीय स्टॉक और प्रवाह का क्षेत्रवार वर्गीकरण



टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित क्षेत्र का कुल आस्तियों में हिस्सेदारी दर्शाते हैं।

* अनुपम प्रकाश, आनंद प्रकाश एक्का, कुणाल प्रियदर्शी, चैताली भौमिक और ईशु ठाकुर, राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक. सुश्री शालिनी जैन ने भी इसमें योगदान दिया है।

वित्तीय स्टॉक और प्रवाह से संबंधित विस्तृत विवरण 1 से 9 को www.rbi.org.in पर अलग से जारी किया गया है।

¹ पहली रिपोर्ट में 1951-52 से 1993-94 की अवधि का डेटा शामिल किया गया था। "भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्टॉक और प्रवाह: 2011-12 से 2017-18" को प्रकाशित करने से पहले (जुलाई 2019 को प्रकाशित) इस लेख का शीर्षक था "भारत का धन प्रवाह खाता", क्योंकि केवल वित्तीय प्रवाह प्रकाशित किए जाते थे।

² हाउसहोल्ड्स में गैर-लाभकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो हाउसहोल्ड्स (एनपीआईएसएच) की सेवा करते हैं जैसे धार्मिक सोसाइटी, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक खेल क्लब, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन आदि। इन संस्थाओं को उनके कम आर्थिक महत्व और जानकारी की कमी के कारण हाउसहोल्ड्स क्षेत्र के साथ जोड़ा जाता है।

इन क्षेत्रों के बीच होने वाले लेनदेनों को नौ वित्तीय लिखतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् (i) मुद्रा; (ii) जमाराशियां; (iii) कर्ज प्रतिभूतियाँ; (iv) ऋण और उधार; (v) इक्विटी; (vi) निवेश फंड (जैसे म्यूचुअल फंड); (vii) बीमा, पेंशन और भविष्य निधि; (viii) मौद्रिक स्वर्ण; और (ix) अन्य खाते (व्यापार कर्ज सहित) और अन्य देयताएं/आस्तियां जो अन्यत्र कहीं वर्गीकृत नहीं हैं (एनईसी)।

इस लेख को छह भागों में विभाजित किया गया है। भाग II वित्तीय खातों के संकलन पर अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रस्तुत करता है। 2019-20 के लिए प्रारंभिक अनुमानों के साथ, 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए क्षेत्रवार वित्तीय संसाधनों में कमी का एक संक्षिप्त विवरण भाग III में दिया गया है। भाग IV में वित्तीय प्रवाहों के क्षेत्रवार मैपिंग पर चर्चा की गई है तथा भाग V में लिखत-वार वित्तीय प्रवाहों को दर्शाया गया है। भाग VI में कतिपय नीति संबंधी दृष्टिकोण पेश किए गए हैं।

II. अंतरराष्ट्रीय अनुभव

वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) ने अक्टूबर 2009 में जी20 डेटा गैप्स इनिशियटिव (डीजीआई), और 2015 में इसके दूसरे चरण का समर्थन किया। इसमें शामिल की गई सिफारिश है 'अन्य (गैर-बैंक) वित्तीय निगम वाले क्षेत्र के डेटा समेत क्षेत्रवार खातों के प्रवाहों और तुलन पत्र के डेटा को अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सांचे के आधार पर तिमाही और वार्षिक अंतराल पर समेकित और प्रचारित करना, तथा तुलन पत्र के विश्लेषण में सहयोग देने के लिए लेनदेन और स्टॉक्स दोनों के लिए किससे-किसको मैट्रिक्स विकसित करना' (आईएमएफ, 2016)। एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू आधार पर उपलब्ध डेटा अंतराल और समयांतर के संदर्भ में अलग-अलग देशों में भिन्न होती है (सारणी 1)।

उदाहरण के लिए, ईएमई में, तुर्की समेकित और असमेकित दोनों फार्मेट में लिखत-वार के साथ-साथ क्षेत्र-वार वर्गीकरण दोनों में एसएनए 2008 का पालन करता है। चीन वित्तीय स्टॉक प्रकाशित नहीं करता है, केवल अंतिम स्रोतों के लिखत-वार वर्गीकरण और प्रत्येक क्षेत्र के उपयोग प्रस्तुत करता है। बेल्जियम, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और यूके से लेकर कोलम्बिया,

सारणी 1: चुनिंदा देशों के वित्तीय स्टॉक और प्रवाह संबंधी डेटा

देश	डेटा प्रकाशन प्राधिकारी	आवधिकता	एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू मैट्रिक
संयुक्त राज्य अमेरिका	यूएस फेडरल रिज़र्व	वार्षिक और तिमाही	हां
यूनाइटेड किंगडम	ऑफिस फॉर नैशनल स्टैटिस्टिक्स	वार्षिक और तिमाही	हां
यूरोपीय संघ	यूरोपियन सेंट्रल बैंक	वार्षिक और तिमाही	हां
तुर्की	टर्कस्टेट और वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय में सेंट्रल बैंक ऑफ द रिपब्लिकन टर्की	वार्षिक और तिमाही	हां
रूस	सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन	वार्षिक और तिमाही	नहीं
इंडोनेशिया	स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया	वार्षिक और तिमाही	नहीं
चीन	पिपल्स बैंक ऑफ चाइना	वार्षिक	नहीं

ब्राजील और इंडोनेशिया तक के देशों ने एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू जानकारी पूरी तरह से न होने की सूचना दी है, जबकि फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास केवल कुछ लिखतों की वार्षिक और तिमाही एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू जानकारी उपलब्ध है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा क्षेत्रवार डेटा की उपलब्धता के संबंध में जी-20 देशों और उसके प्रमुख ऐक्सेशन साझेदारों के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 13 यूरोपीय देशों व एक गैर-यूरोपीय देश, अर्थात्, ऑस्ट्रेलिया के पास सभी प्रमुख आठ लिखतों के संबंध में तिमाही के साथ-साथ वार्षिक अंतराल पर एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू डेटा उपलब्ध थे।

III. क्षेत्रवार वित्तीय संसाधनों में कमी

भारत में, एफएसएफ खाते के संकलन के लिए आवश्यक तुलन पत्र डेटा को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग अंतराल³ पर जारी किया जाता है। क्षेत्रवार वित्तीय संसाधन की स्थिति बताती है कि हाउसहोल्ड्स (एचएच), वित्तीय निगमों और निजी गैर-वित्तीय निगमों (निजी एनएफसी) के पास धनात्मक वित्तीय निवल मालियत थी, जबकि 2011-12 से 2019-20 की अवधि के दौरान सामान्य सरकार और सरकारी गैर-वित्तीय निगम

³ एनएफसी, सामान्य सरकार, पेंशन और भविष्य निधि, बीमा जैसे क्षेत्रों के तुलन पत्र डेटा, एक वर्ष से अधिक अंतराल के बाद उपलब्ध हो जाते हैं; अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के मामले में यह अंतराल 9 महीने है; और म्यूचुअल फंड, आरओडब्ल्यू तथा आरबीआई के मामले में यह 3 महीने तक के अंतराल पर उपलब्ध हो जाता है।

(सरकारी एनएफसी) की ऋणात्मक वित्तीय निवल मालियत थी (सारणी 2)। साथ ही, इस अवधि में जीजी और सरकारी एनएफसी दोनों के मामले में वित्तीय निवल मालियत में गिरावट आई है, जबकि निजी एनएफसी की स्थिति 2018-19 के दौरान बिगड़ने के बाद स्थिर हो गयी। हालांकि, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 2019-20 के दौरान हाउसहोल्ड्स की वित्तीय निवल मालियत में सुधार हुआ है।

संसाधनों के निवल प्रवाह के संदर्भ में, गैर-वित्तीय निगम और सामान्य सरकार प्रमुख घाटे वाले क्षेत्र हैं, जबकि वित्तीय निगम और हाउसहोल्ड्स (एचएच) प्रमुख अधिशेष वाले क्षेत्र हैं। गैर-वित्तीय निगमों के निवल उधार में वृद्धि और हाउसहोल्ड की

बचत में कमी की वजह से अर्थव्यवस्था के समग्र वित्तीय संसाधन शेष में 2018-19 के दौरान गिरावट आई, जिसे मापने के लिए देयताओं पर हुए निवल खर्च को वित्तीय आस्तियों के निवल अधिग्रहण से घटाया जाता है (सारणी 3)। सामान्य सरकार और सरकारी गैर-वित्तीय निगमों के संसाधनों के बढ़ते घाटों के कारण 2018-19 में समग्र वित्तीय संसाधन शेष की मामूली अधिशेष स्थिति 2019-20 में घाटे में तबदील हो गई।

IV. क्षेत्रवार वित्तीय शेष और ट्रेजेक्ट्रीस⁴

प्रत्येक क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का विश्लेषण, जो अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़े गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करते हैं।

सारणी 2: क्षेत्रवार वित्तीय मालियत
(मौजूदा बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
आस्तियां									
1 वित्तीय निगम	222.7	225.4	227.1	229.3	229.9	228.9	233.3	233.0	239.4
2 गैर-वित्तीय निगम	132.7	123.9	123.2	122.9	117.1	106.7	94.3	90.6	89.5
2.ए सरकारी गैर-वित्तीय निगम	18.1	17.1	16.2	15.3	11.9	11.6	12.2	11.1	10.8
2.बी निजी गैर-वित्तीय निगम	114.6	106.8	107.0	107.5	105.2	95.0	82.1	79.5	78.7
3 सामान्य सरकार	31.5	30.9	30.3	28.8	30.0	30.1	30.3	29.9	30.6
4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	135.9	132.5	129.8	130.1	129.4	128.3	130.1	131.3	134.5
5 शेष विश्व	46.0	48.0	50.1	50.6	49.7	45.6	45.2	40.8	45.8
देयताएं									
1 वित्तीय निगम	189.3	190.8	192.2	194.1	194.8	193.2	197.5	197.2	204.0
2 गैर-वित्तीय निगम	110.0	105.0	106.1	107.2	103.6	94.5	85.3	83.2	83.6
2.ए सरकारी गैर-वित्तीय निगम	19.6	20.4	21.3	22.1	20.8	21.5	22.2	21.8	23.0
2.बी निजी गैर-वित्तीय निगम	90.4	84.6	84.8	85.1	82.8	73.0	63.0	61.4	60.6
3 सामान्य सरकार	77.8	77.5	77.3	76.8	78.8	78.8	79.6	79.6	82.6
4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	39.1	38.4	37.7	37.4	36.9	36.6	37.8	38.3	39.1
5 शेष विश्व	23.3	22.4	23.8	24.5	24.6	22.3	22.7	21.8	25.3
वित्तीय मालियत									
1 वित्तीय निगम	33.4	34.6	34.9	35.2	35.1	35.7	35.8	35.8	35.3
2 गैर-वित्तीय निगम	22.6	18.8	17.2	15.6	13.5	12.1	9.1	7.4	5.9
2.ए सरकारी गैर-वित्तीय निगम	-1.5	-3.3	-5.0	-6.8	-8.9	-9.9	-10.0	-10.7	-12.2
2.बी निजी गैर-वित्तीय निगम	24.2	22.1	22.2	22.4	22.4	22.0	19.1	18.1	18.1
3 सामान्य सरकार	-46.3	-46.6	-47.1	-48.0	-48.8	-48.7	-49.2	-49.7	-52.1
4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	96.8	94.1	92.2	92.7	92.5	91.6	92.3	93.0	95.4
5 शेष विश्व	22.7	25.6	26.3	26.1	25.1	23.3	22.5	18.9	20.5

टिप्पणी : वित्तीय मालियत की गणना बकाया आस्तियों और देयताओं (शेयरधारकों की इक्विटी को छोड़कर) के बीच अंतर के रूप में की जाती है।

#: संबंधित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध प्रमुख संकेतकों पर आधारित प्रारंभिक अनुमान। तुलन पत्र डेटा की उपलब्धता में देरी के कारण, 2019-20 के लिए एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू सारणियों का क्षेत्रवार संकलन संभव नहीं है।

⁴ यह भाग केवल 2018-19 तक के रुझानों पर केंद्रित है, जिसके लिए क्षेत्र वार और लिखत वार एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू खातों को संकलित किया गया है।

**सारणी 3: क्षेत्रवार वित्तीय संसाधन शेष
(मौजूदा बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत)**

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20#
1 वित्तीय निगम	3.0	2.6	2.5	1.8	2.3	1.9	1.8	0.3
2 गैर-वित्तीय निगम	-8.9	-6.4	-5.7	-5.2	-3.2	-2.3	-4.2	-5.0
2.ए सरकारी गैर-वित्तीय निगम	-2.8	-2.6	-2.8	-3.1	-2.5	-2.0	-2.2	-3.0
2.बी निजी गैर-वित्तीय निगम	-6.2	-3.8	-2.9	-2.1	-0.7	-0.4	-2.0	-2.0
3 सामान्य सरकार	-5.7	-5.8	-5.6	-5.4	-5.1	-5.4	-5.3	-5.7
4 हाउसहोल्ड क्षेत्र	8.4	8.4	8.0	9.1	8.4	8.7	8.2	8.7
5 कुल (1+2+3+4)	-3.3	-1.2	-0.8	0.3	2.4	2.8	0.5	-1.8

टिप्पणी : वित्तीय संसाधन शेष की गणना निवल वित्तीय आस्तियों और निवल वित्तीय देयताओं (शेयरधारकों की इक्विटी सहित) के प्रवाह के बीच अंतर के रूप में की जाती है। यहां देयताओं में शेयरधारकों की इक्विटी भी शामिल होने की वजह से वित्तीय संसाधन शेष लगातार दो वर्षों की मालियत के बीच अंतर के बराबर नहीं होगा।

#: संबंधित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध प्रमुख संकेतकों पर आधारित प्रारंभिक अनुमान। तुलन पत्र डेटा की उपलब्धता में देरी के कारण, 2019-20 के लिए एफडब्ल्यूटीडब्ल्यू सारणियों का क्षेत्रवार संकलन संभव नहीं है।

IV.1 वित्तीय निगम

वित्तीय निगमों में, अन्य निक्षेपागार निगम (ओडीसी)⁵ कुल आस्तियों के 52 प्रतिशत होते हैं, जिसके बाद अन्य वित्तीय निगम (ओएफसी)⁶ (38 प्रतिशत) एवं केंद्रीय बैंक (10 प्रतिशत) का स्थान आता है, इसमें परवर्ती को मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता की जिम्मेदारी को देखते हुए ओडीसी से अलग रखा गया है। निक्षेपागार संस्थाओं में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 44 प्रतिशत की प्रबल हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बैंक-आधारित स्वरूप पर प्रकाश डालती है। ओएफसी में, एफसी क्षेत्र की कुल आस्तियों में बीमा की सबसे अधिक 11 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसके बाद जमाराशि स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) (7 प्रतिशत), म्यूचुअल फंड (6 प्रतिशत) और भविष्य निधि एवं पेंशन फंड (5 प्रतिशत) का स्थान आता है (चार्ट 1)।

IV.1.1 केंद्रीय बैंक

2018-19 में रिजर्व बैंक के तुलन पत्र⁷ का आकार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मामूली रूप से घट गया। हालांकि, रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली-स्तर की चलनिधि को बढ़ाने के लिए किए गए

विभिन्न उपायों की बदौलत 2019-20 के दौरान इसका काफी विस्तार हुआ है (चार्ट 2)।

भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य देयता परिचालनगत मुद्रा है, जिसमें से लगभग 95 प्रतिशत हाउसहोल्ड क्षेत्र के पास है। 2018-19 में मुद्रा में हुई वृद्धि 2017-18 की तुलना में बहुत कम थी – जो पुनर्मुद्रीकरण और विनिर्दिष्ट बैंकनोटों (एसबीएन) के प्रसंस्करण और निपटान का वर्ष था।

केंद्रीय बैंक की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण देयता जमाराशि होती है, जो अधिकांशतः बैंकों की आस्तियां होती हैं, जिसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) अपेक्षाओं और भुगतान और निपटान दायित्वों (आरबीआई, 2019ए) को पूरा करने के लिहाज से उनके चालू खातों में बतौर शेष रखी जाती हैं। समग्र दृष्टि से देखें तो रिजर्व बैंक के पास रखी गई बैंकों की कुल जमाराशियों में 2018-19 में लगातार दूसरे साल गिरावट आई। जहां उच्च जमा संग्रहण की वजह से रिजर्व बैंक के पास रखी गई बैंकों की जमाराशियों में इजाफा हुआ, वहीं रिवर्स रेपो के अंतर्गत जमाराशियों में गिरावट आने से इसकी लगभग भरपाई हो गई।

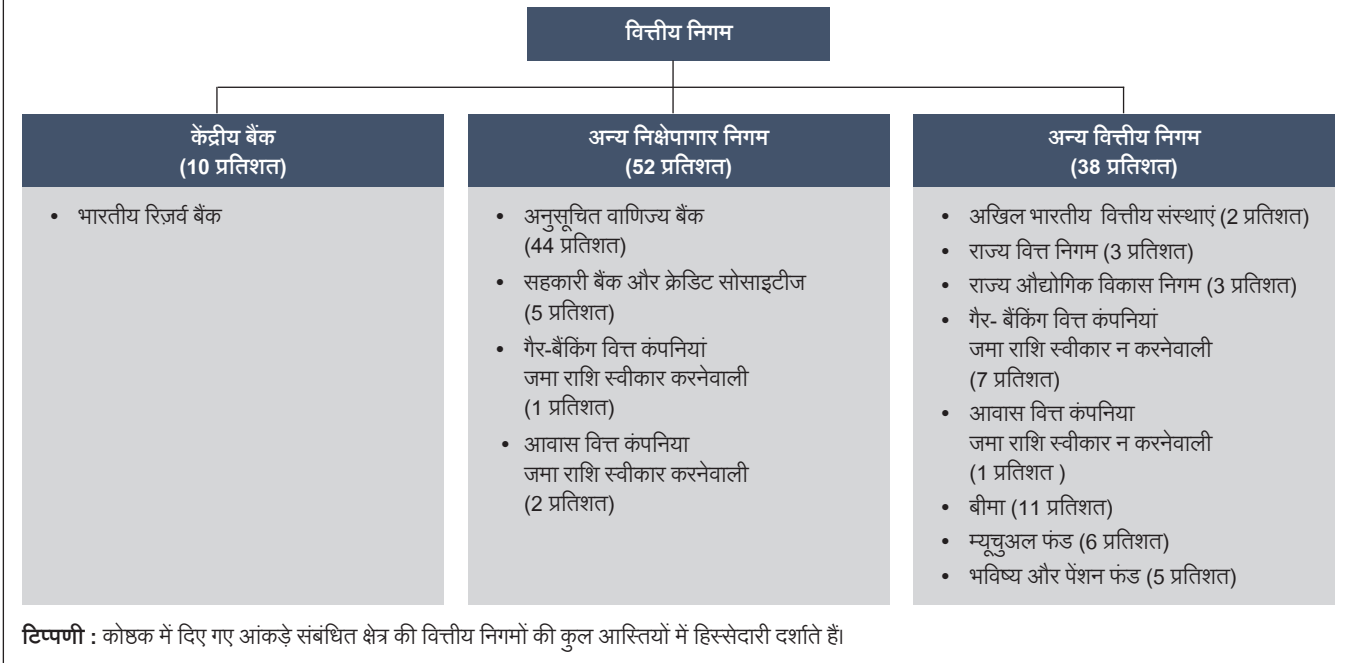
आस्ति पक्ष में देखें तो, कर्ज प्रतिभूतियां प्रमुख लिखत होते हैं जो शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान रिजर्व बैंक के घरेलू निवेश में 45.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इसके चलनिधि संचालन कार्यों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों की निवल खरीद के कारण हुई। रिजर्व बैंक द्वारा अन्य निक्षेपागार निगमों को दिए गए ऋणों में 2018-19 में एक साल पहले की तुलना में तेजी से कमी आई है, जो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में संपार्श्विक के रूप में रेपो/

⁵ भारत के मामले में, ओडीसी में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा जमाराशि लेने वाली आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं।

⁶ अन्य वित्तीय निगमों (ओएफसी) में आने वाले प्रमुख इकाइयों को उनके संबंधित हिस्सेदारियों के क्रम में इस प्रकार रखा गया है - बीमा, म्यूचुअल फंड (एमएफ), भविष्य निधि और पेंशन फंड, जमाराशि नहीं लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एआईएफआई), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी), राज्य वित्त निगम (एसएफसी) और जमाराशि नहीं लेने वाली आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी-एनडी)।

⁷ इस लेख में तुलन पत्र का आशय वित्तीय तुलन पत्र से है, जिसमें अचल संपत्ति, प्रावधान और आस्थगित कर शामिल नहीं है।

चार्ट 1: वित्तीय निगम के संघटक : 2018-19

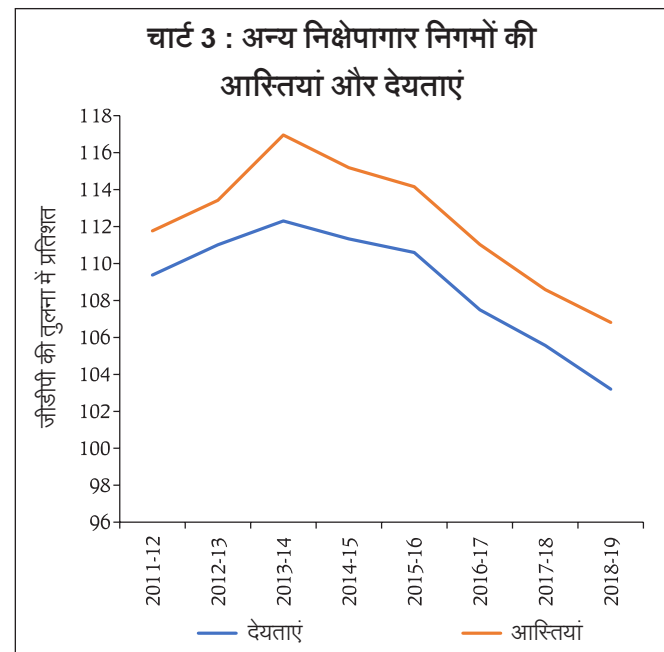
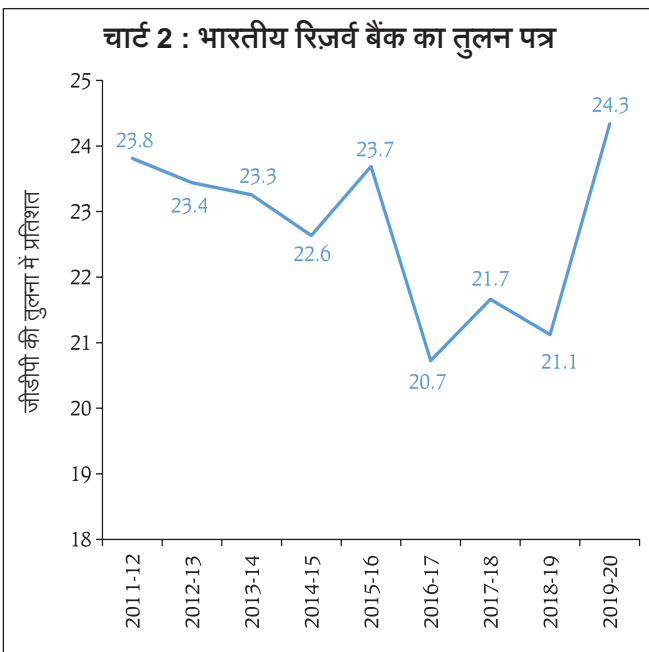


टर्म रेपो/सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत चलनिधि सुविधा के कम उपयोग को दर्शाती है।

IV.1.2 अन्य निक्षेपागार निगम (ओडीसी)

प्रमुख क्षेत्र होने के बावजूद अन्य निक्षेपागार निगमों के तुलन पत्र में 2013-14 के बाद से गिरावट महसूस की गई, जो

जमाराशियों के स्थान पर म्यूचुअल फंड और बीमा जैसे अन्य आकर्षक वित्तीय लिखतों को लेकर उनकी पसंद में आए बदलाव को दर्शाती है (चार्ट 3)। ओडीसी क्षेत्र के भीतर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और जमाराशि स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) अपनी वित्तीय मध्यस्थता की भूमिकाओं में पूरकता प्रदर्शित करती हैं। दृढ़ ऋण विस्तार की



बदौलत एनबीएफसी का समेकित तुलन पत्र परवान चढ़ा, जिसे बैंकों की अपेक्षा एनपीए का स्तर कम होने तथा 2016-17 और 2017-18 के दौरान एक मजबूत पूंजी बफर का सहारा मिला (आरबीआई, 2019बी)। हालांकि, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) संकट द्वारा प्रेरित चलनिधि संकट एवं तत्पश्चात एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा रेटिंग में गिरावट से जूझने के कारण 2018-19 के दौरान एनबीएफसी-डी से होने वाले ऋण बहिर्वाह में कमी आई।

अन्य निक्षेपागार निगमों (ओडीसी) की देयताएं

हाउसहोल्ड्स की जमाराशियां देयता पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण लिखत होती हैं, जिसके बाद ओएफसी से प्राप्त ऋण का स्थान आता है (चार्ट 4)। विमुद्रीकरण के वर्ष को छोड़ दिया जाए तो 2009-10 के बाद से जमा संग्रहण में निरंतर गिरावट आई, जिसे उच्च ब्याज दरों समेत संसाधन जुटाने के लिए बैंकों के बीच चल रहे अत्यधिक होड़ की बदौलत रोका गया। उच्च जमा संग्रहण के कारण ओडीसी क्षेत्र की उधारी में गिरावट आई (आरबीआई, 2019बी)। वैश्विक आर्थिक मंदी और पूंजी प्रवाह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर लौटने के परिणामस्वरूप 2018-19 के दौरान शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) के प्रति ओडीसी की देयताएं संकुचित हुईं।

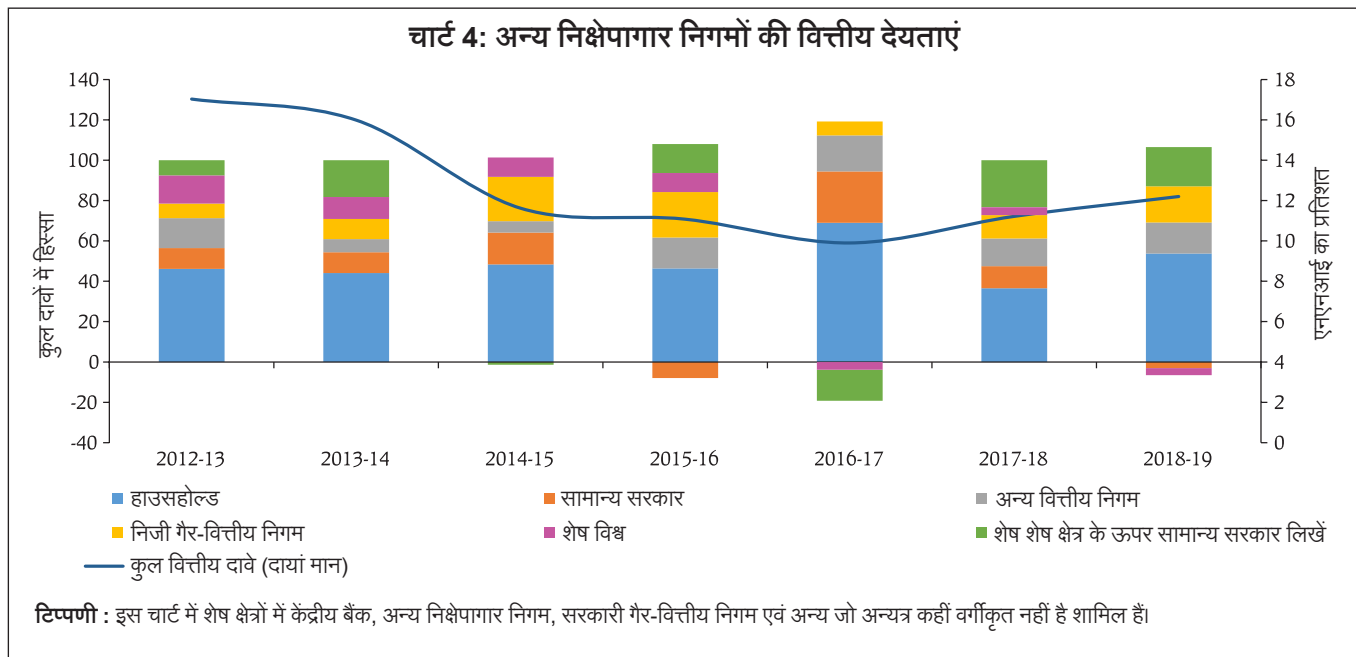
अन्य निक्षेपागार निगमों (ओडीसी) की आस्तियां

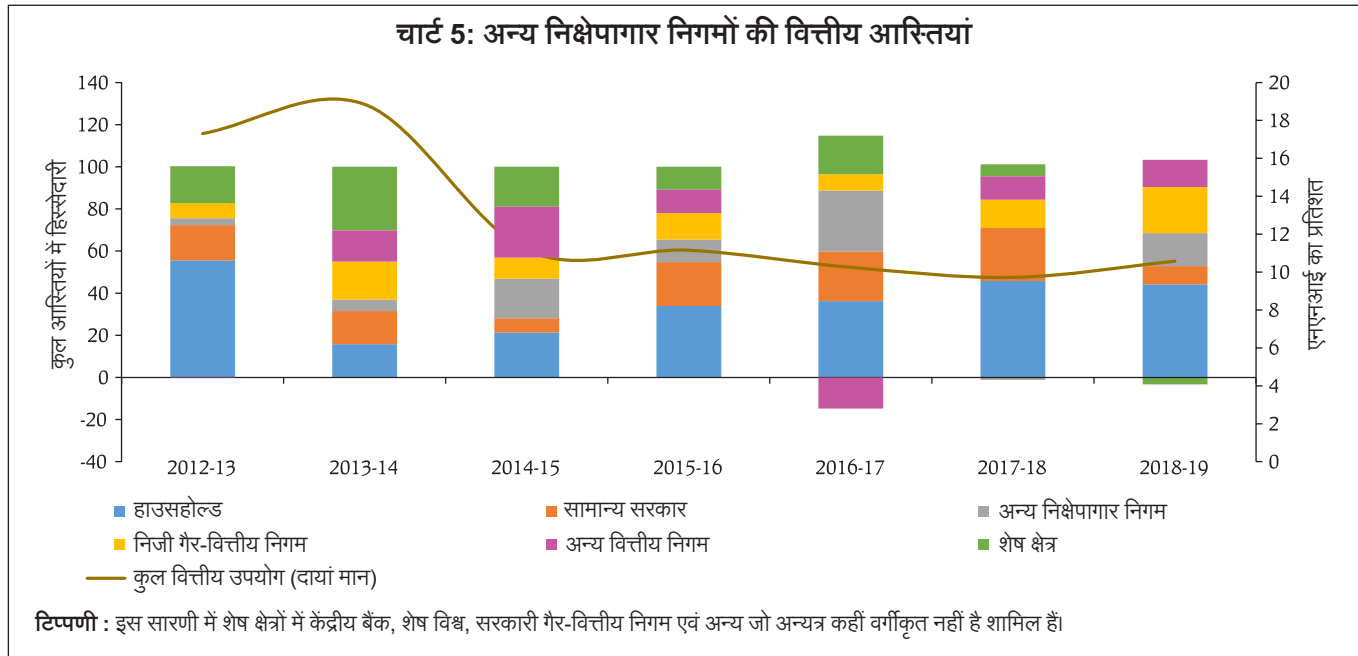
आस्ति पक्ष में, हाउसहोल्ड्स और गैर-वित्तीय निगमों को प्रदत्त ऋण और अग्रिम सबसे महत्वपूर्ण लिखत बने हुए हैं, जिसके बाद सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का स्थान आता है (चार्ट 5)। ऋणों और अग्रिमों के संवितरण ने 2017-18 में जोर पकड़ा और उसने 2018-19 में अपने गति को बनाए रखा। इसे अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को तकरीबन पूरी तरह से पहचानने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूजीकरण एवं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) (आरबीआई, 2019बी) के तहत जारी समाधान प्रक्रिया की बदौलत ऋण परिवेश में सुधार होने से सहारा मिला।

इस क्षेत्र की समग्र वित्तीय निवल मालियत में सात वर्षों के अंतराल के बाद 2018-19 में मामूली सुधार हुआ, जिसका मुख्य कारण एससीबी की आस्ति गुणवत्ता का बेहतर होना था।

IV.1.3 अन्य वित्तीय निगम (ओएफसी)

भारत में, अन्य वित्तीय निगम (ओएफसी) क्षेत्र के तुलन पत्र का आकार एफसी की कुल आस्ति का 38 प्रतिशत है। 2018-19 में इसका विस्तार जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लिखतों



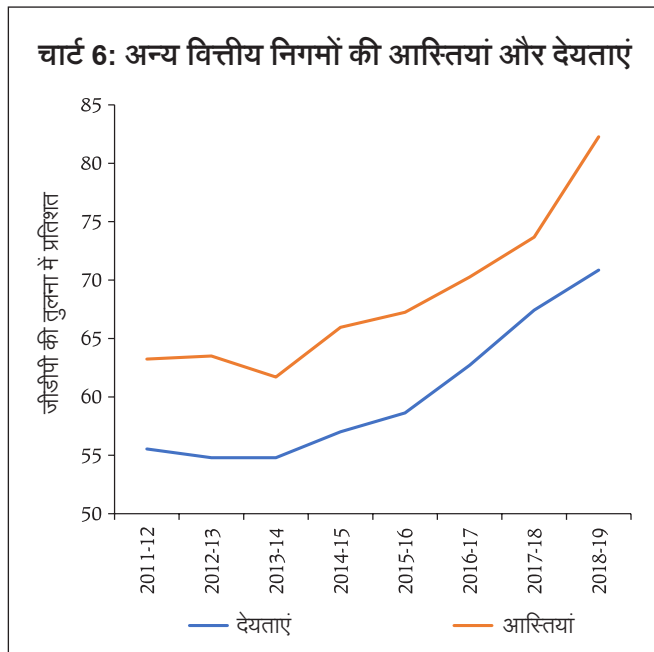


के लिए प्राथमिकता बदलती रही, जैसा कि पिछले भाग में चर्चा की गई है (चार्ट 6)।

आईएल और एफसी संकट के बाद, डिबेंचर के माध्यम से संसाधन जुटाना महंगा पड़ा और चूंकि जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी) को लेकर निवेशक के विश्वास में भारी कमी आई इसलिए उनको बैंक

से उधार लेना पड़ा (आरबीआई, 2019बी)। वर्ष 2018-19 के दौरान ओएफसी पर अन्य निक्षेपागार निगमों के उच्च वित्तीय दावों से इसका पता चलता है (चार्ट 7)।

उनके तुलन पत्र के आस्तिक पक्ष में सरकारी कर्ज प्रतिभूतियों का बाहुल्य है और उसके बाद सरकारी गैर-वित्तीय निगमों को जारी ऋण एवं ओडीसी क्षेत्र के पास रखी गई जमाराशियां का स्थान आता है (चार्ट 8)।

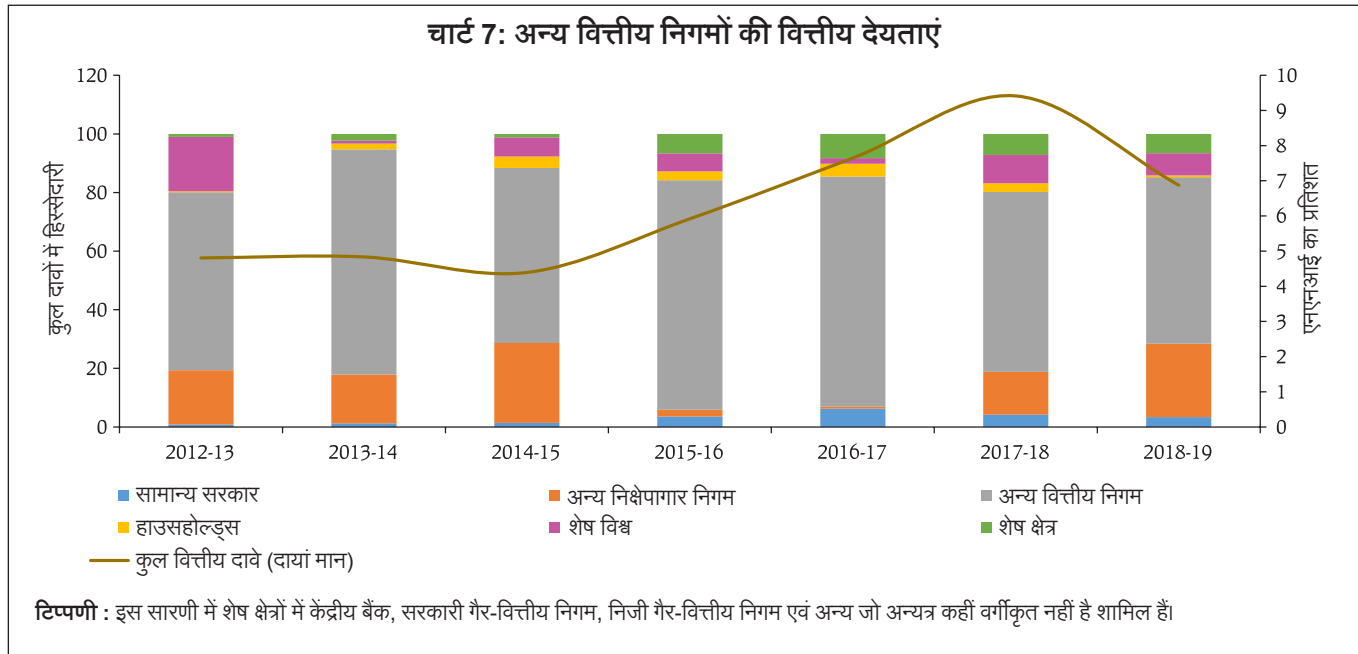


वित्तीय प्रवाहों को लेन-देन एवं मूल्यांकन परिवर्तन⁸ में विभाजित करने से पता चलता है कि 2016-17 से 2018-19 के दौरान ओएफसी क्षेत्र की आस्तियों में औसतन 26 प्रतिशत परिवर्तन उसकी आस्तियों की मूल्यवृद्धि की वजह से है (विवरण 3.1)।

IV.2 गैर-वित्तीय निगम (एनएफसी)

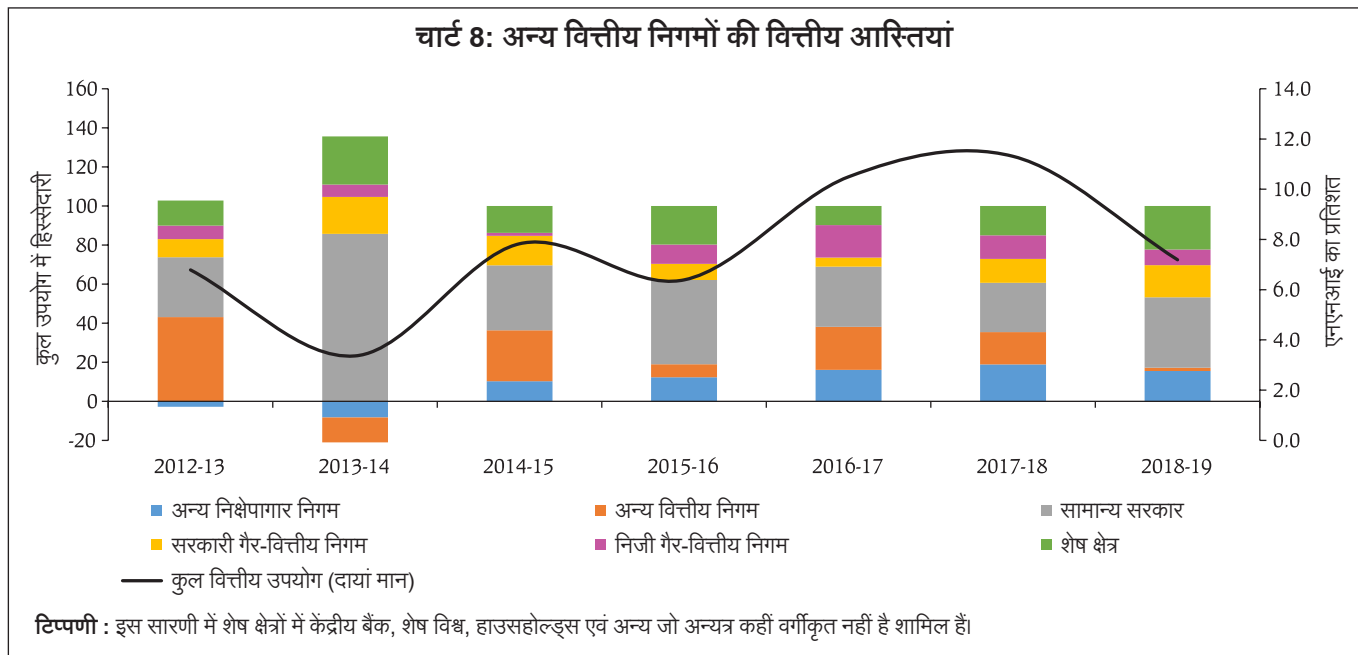
गैर-वित्तीय निगम लाभप्रद आस्तियों में निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था की वृद्धि में सहयोग देते हैं, जिनका अर्थव्यवस्था की कुल वित्तीय आस्तियों में लगभग 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है और

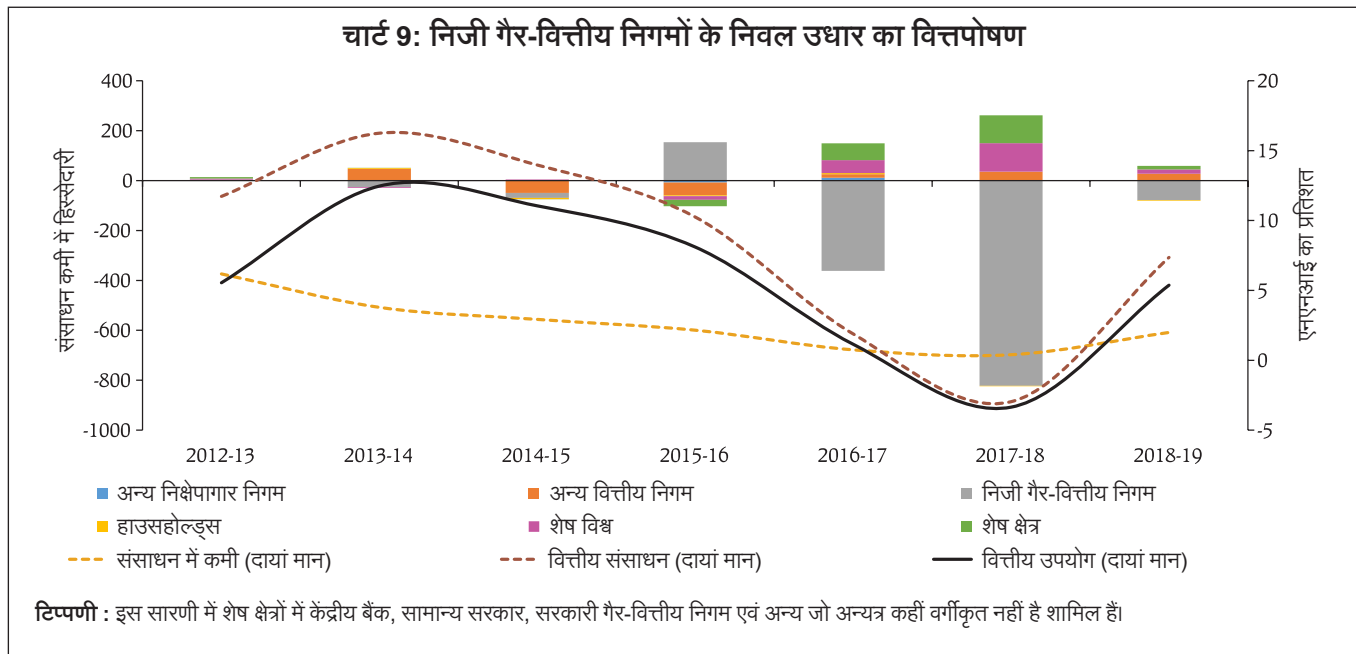
⁸ प्रवाहों को लेन-देन और मूल्यांकन परिवर्तन में विभाजित करने का प्रयास किया गया है, जो चुनिंदा उप-क्षेत्रों, अर्थात्, म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन और भविष्य निधि के लिए डेटा की उपलब्धता पर निर्भर करता है।



जिनमें सरकारी गैर-वित्तीय निगम एवं निजी गैर-वित्तीय निगम शामिल हैं। निजी गैर-वित्तीय निगमों की वित्तीय आस्तियों में तेजी से कमी आने की वजह से 2018-19 में एनएफसी की वित्तीय निवल मालियत में गिरावट जारी रही (सारणी 2)। सरकारी गैर-वित्तीय निगमों की विद्यमान ऋणात्मक निवल मालियत खस्ताहाल केंद्रीय सरकारी क्षेत्र इकाइयों (सीपीएसयू) के खराब कार्य-निष्पादन को दर्शाती है।

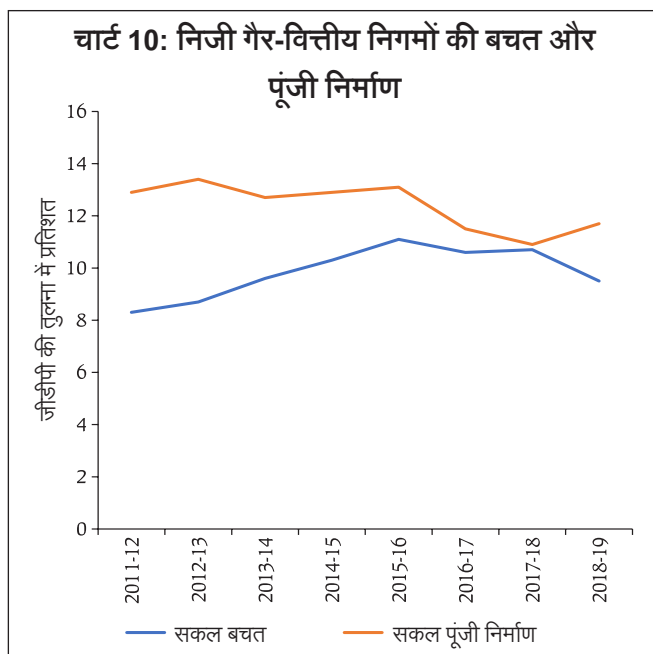
गैर-वित्तीय निगमों में, निजी इकाइयों की पसंद इक्विटी वित्त (संसाधनों का 44 प्रतिशत) है, जबकि सरकारी इकाइयों की पसंद बाह्य वित्त के तौर पर ऋण और उधार हैं। लाभांश वितरण कर से बचने के उद्देश्य से कई फर्मों द्वारा शेयरों की वापसी खरीद के कारण 2017-18 के दौरान निजी एनएफसी में इक्विटी प्रवाह ऋणात्मक हो गए थे। वर्ष 2018-19 में, उन्होंने जीएमआर छत्तीसगढ़ और उभरते बिजली उपक्रमों जैसे बदहाल बिजली क्षेत्र





उद्यमों के मामले में प्रमुख रूप से बकाया ऋणों को इक्विटी में बदलने के जरिए कारोबार पुनः आरंभ किया (चार्ट 9)।

निजी निगमों के संसाधनों की कमी 2017-18 के 0.2 प्रतिशत से 2018-19 में बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गई, क्योंकि ऋण और उधार रूपी प्रवाहों में वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 10)। सरकारी निगमों के मामले में भी संसाधनों की कमी 2018-19 में बढ़ी (चार्ट 11)।



IV.3 सामान्य सरकार⁹

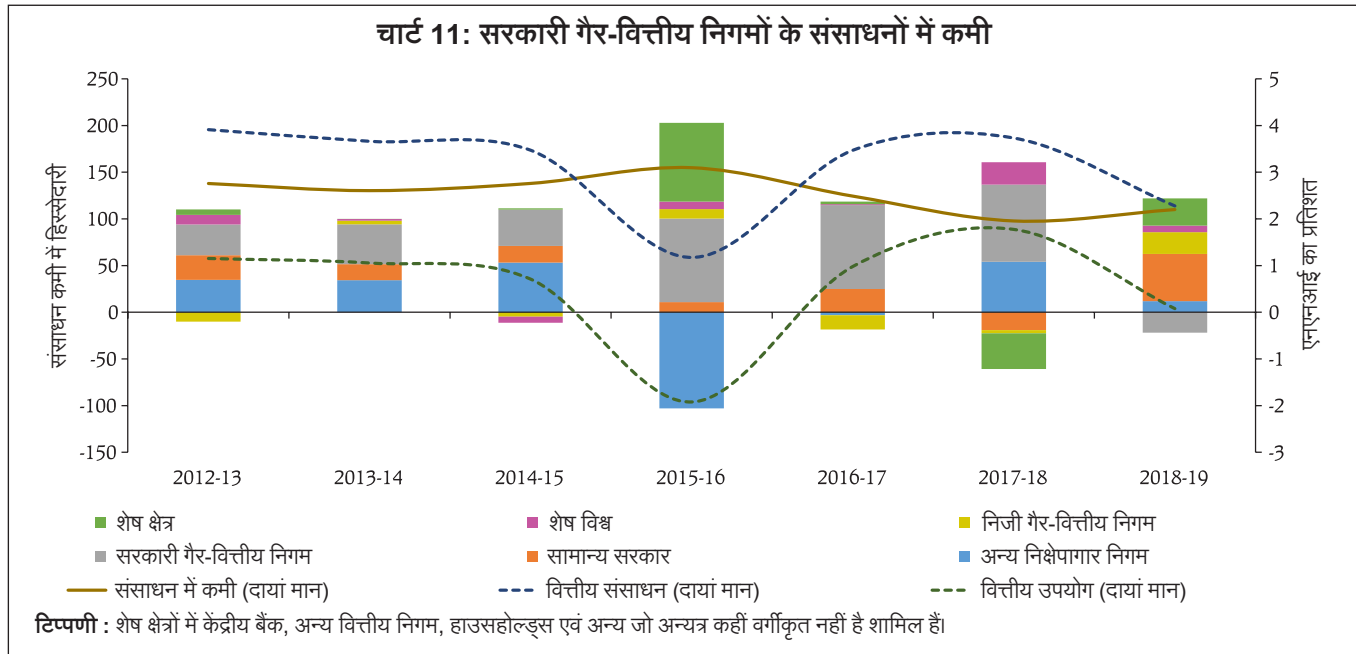
भारत में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही घाटे में चल रही हैं एवं अर्थव्यवस्था में निवल उधारकर्ता हैं। वर्ष 2018-19 में सामान्य सरकार की देयताओं का स्तर बढ़ा रहा, जिसमें कर्ज प्रतिभूतियों का बाहुल्य था, जो 2018-19 में कुल देयताओं का लगभग 83 प्रतिशत है – जिसकी दो-तिहाई ओडीसी और ओएफसी द्वारा अभिदत्त थी (विवरण 3.1 और चार्ट 12)।

आस्तित्व पक्ष में, पीएसयू में इक्विटी धारिता की सर्वाधिक हिस्सेदारी है और उसके बाद ओडीसी के पास रखी गई जमाराशियों का स्थान आता है। औसतन, सामान्य सरकार की आस्तियों का लगभग 82 प्रतिशत इक्विटी के रूप में धारित किया जाता है। जमाराशियों के रूप में ओडीसी के पास रखी गई आस्तियां राज्य सरकारों के मामले में अधिक स्पष्ट हैं, जिसमें विशाल नकदी शेष संचित हो गया था, जो खराब नकदी प्रबंधन को दर्शाता है।

IV.4 हाउसहोल्ड्स और एनपीआईएसएच

हाउसहोल्ड्स आम तौर पर निवल बचतकर्ता और निवल ऋणदाता होते हैं तथा धनात्मक वित्तीय निवल मालियत रखते हैं। हाउसहोल्ड क्षेत्र का निवल वित्तीय अधिशेष, देयताओं की तुलना

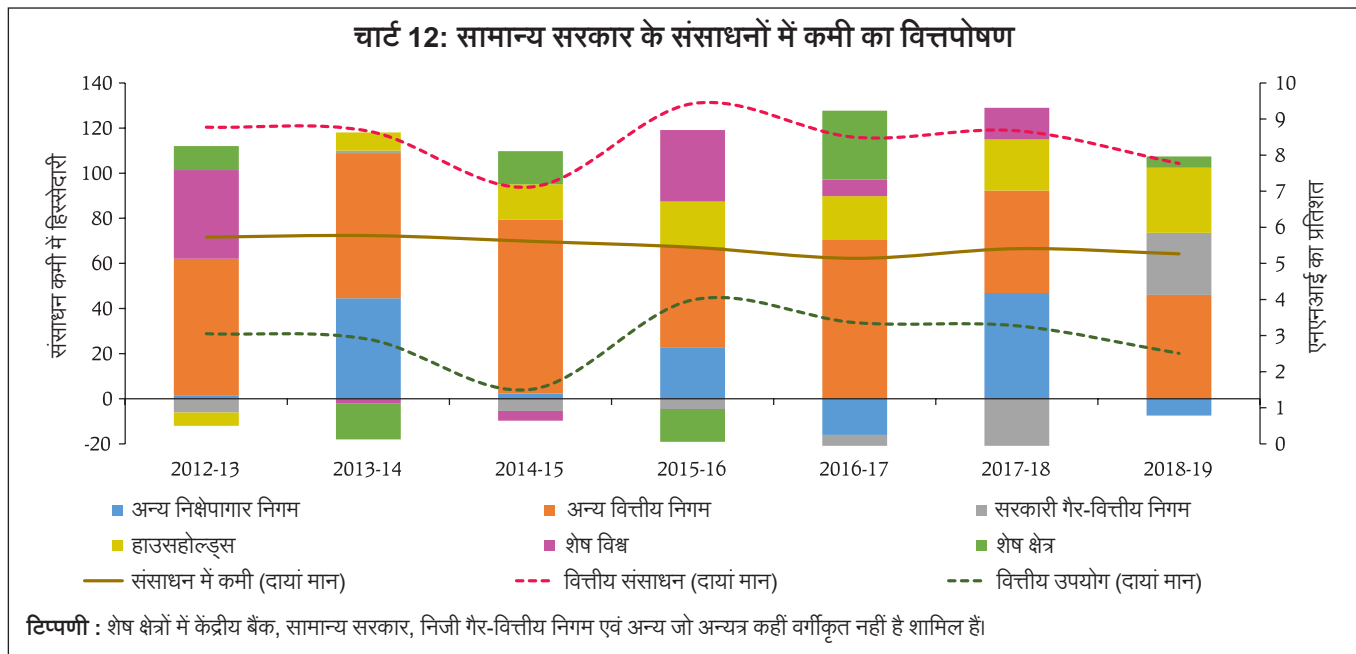
⁹ सामान्य सरकार में केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारें शामिल हैं। डेटा के अभाव में, स्थानीय निकायों के लिए संकलन नहीं किया जाता है जो सामान्य सरकारी क्षेत्र का तीसरा टियर होता है।



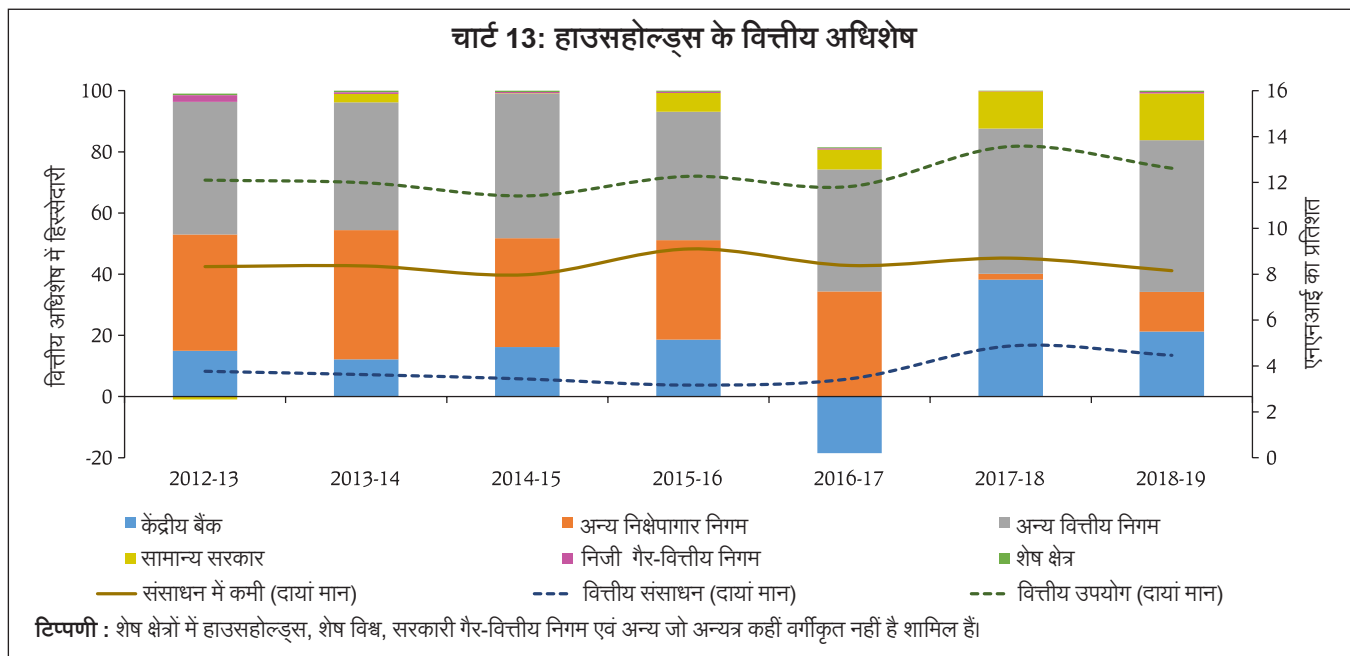
में वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण में काफी कमी आने की वजह से गत वर्ष¹⁰ में 8.7 प्रतिशत से 2018-19 में घटकर निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) का 8.2 प्रतिशत रह गया (चार्ट 13)।

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण और उधार लेना हाउसहोल्ड्स की देयताओं के प्राथमिक घटक होते हैं, जबकि

हाउसहोल्ड्स की आस्तियां अधिकांशतः जमाराशियों, बीमा और मुद्राओं के रूप में धारित हैं। हाल के वर्षों में हाउसहोल्ड्स द्वारा बकाया ऋण और उधार निरंतर वृद्धि प्रदर्शित करते हैं जो 2016-17 में जीडीपी के 32.0 प्रतिशत से क्रमिक रूप से बढ़कर 2018-19 में जीडीपी का 33.8 प्रतिशत हो गया। यह इसी अवधि में



¹⁰ विभिन्न विभाजक का उपयोग करने से, एनएनआई के 8.2 प्रतिशत पर हाउसहोल्ड्स निवल वित्तीय अधिशेष हाल ही में प्रकाशित हाउसहोल्ड्स वित्तीय बचत से अलग है, जो 2018-19 में जीडीपी का 7.2 प्रतिशत है।



घटती संपूर्ण ऋण वृद्धि के विपरीत है क्योंकि एससीबी ने इसे खुदरा ऋणों में एनपीए कम होने की वजह से औद्योगिक ऋणों की अपेक्षा प्राथमिकता दी (आरबीआई, 2019बी)।

आस्तित्व पक्ष में, जमाराशियों का हाउसहोल्ड्स की आस्तियों में लगभग आधा हिस्सा होता है, जिसकी कुल आस्तियों में हिस्सेदारी स्थिर रहती है। मुद्रा धारिता 2018-19 के दौरान विमुद्रीकरण-पूर्व के स्तर पर पहुंची, जिसमें विमुद्रीकरण और तत्पश्चात के पुनर्मुद्रीकरण की वजह से 2016-17 और 2017-18 के दौरान काफी उतार-चढ़ाव आया। कर्ज प्रतिभूतियों में बीमा, पेंशन फंड और निवेश के अधिग्रहण में सतत वृद्धि हुई।

IV.5 शेष विश्व

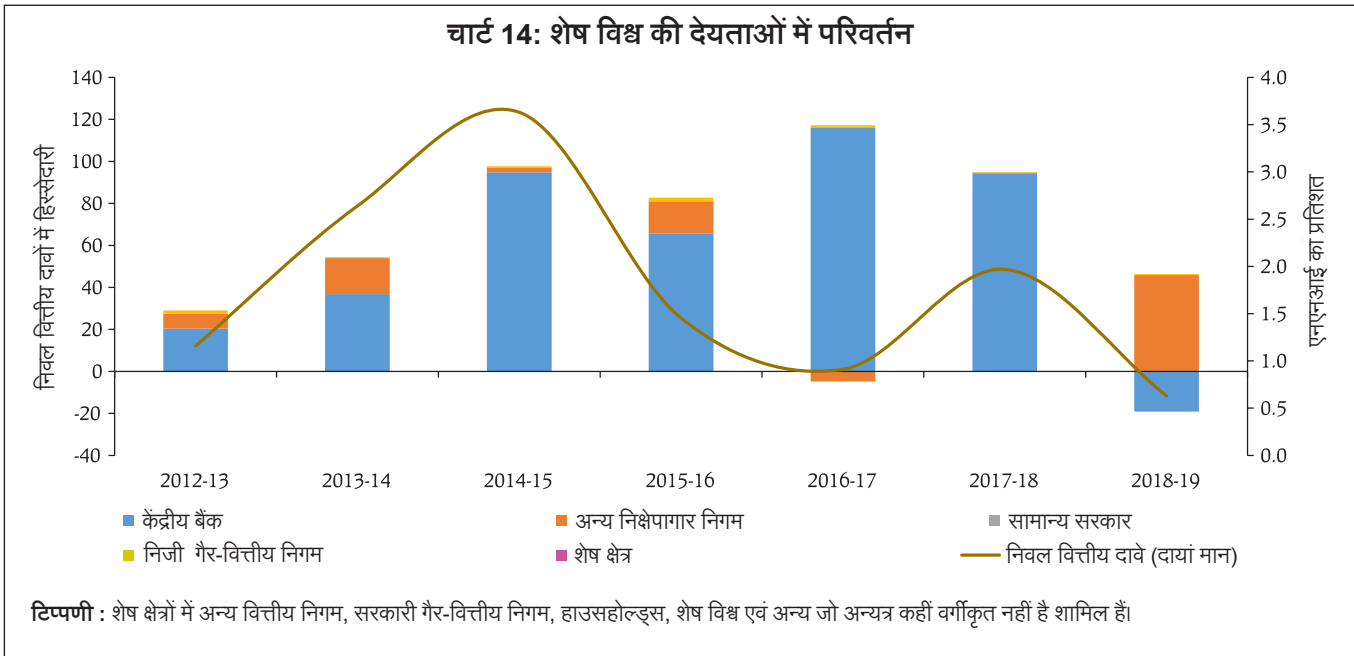
भारत शेष विश्व (आरओडब्ल्यू) से उधार लेने के मामले में निवल उधारकर्ता है, जिसका निवल उधार समय के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है। कर्ज प्रतिभूतियों का निर्गम आरओडब्ल्यू के धन का प्रमुख स्रोत है, जो प्रमुख रूप से केंद्रीय बैंक और निजी कॉर्पोरेट द्वारा अभिदत्त है (चार्ट 14)।

दूसरी तरफ, आरओडब्ल्यू की अधिकांश आस्तियां इक्विटी और कर्ज प्रतिभूतियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश के रूप में होने के साथ-साथ भारतीय कॉर्पोरेट को प्रदत्त ऋण तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित जमाराशियों के रूप में हैं (चार्ट 15)। संयुक्त राज्य अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति के

परिणामस्वरूप वृहद अपविक्रय की वजह से 2018-19 के दौरान इक्विटी और कर्ज लिखतों के अंतर्गत प्रवाहों में कमी आई तथा मंदी व्याप्त होने की ज्यादा संभावना दिखती है। वर्ष 2018-19 में भारतीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त ऋण और उधार पांच वर्षों में सर्वोच्च रहा जो घरेलू बाजार में उच्च ब्याज दर, एवं उच्च अनर्जक आस्तियों के फलस्वरूप घरेलू ऋणदाताओं में बढ़ती जोखिम विमुखता दर्शाता है। तथापि, जीडीपी के अनुपात के रूप में आरओडब्ल्यू से निवल उधार लगातार चार वर्षों के लिए कम होता गया। कुल मिलाकर, 2019-20 के दौरान जीडीपी के अनुपात के रूप में आरओडब्ल्यू से निवल उधार घटा। अन्य प्रमुख रुझानों में दृढ़ इक्विटी प्रवाह, व्यापार ऋण और अग्रिमों में कमी तथा विदेश में जारी की गई कर्ज प्रतिभूतियों के रिजर्व बैंक द्वारा अभिदान में इजाफा शामिल हैं।

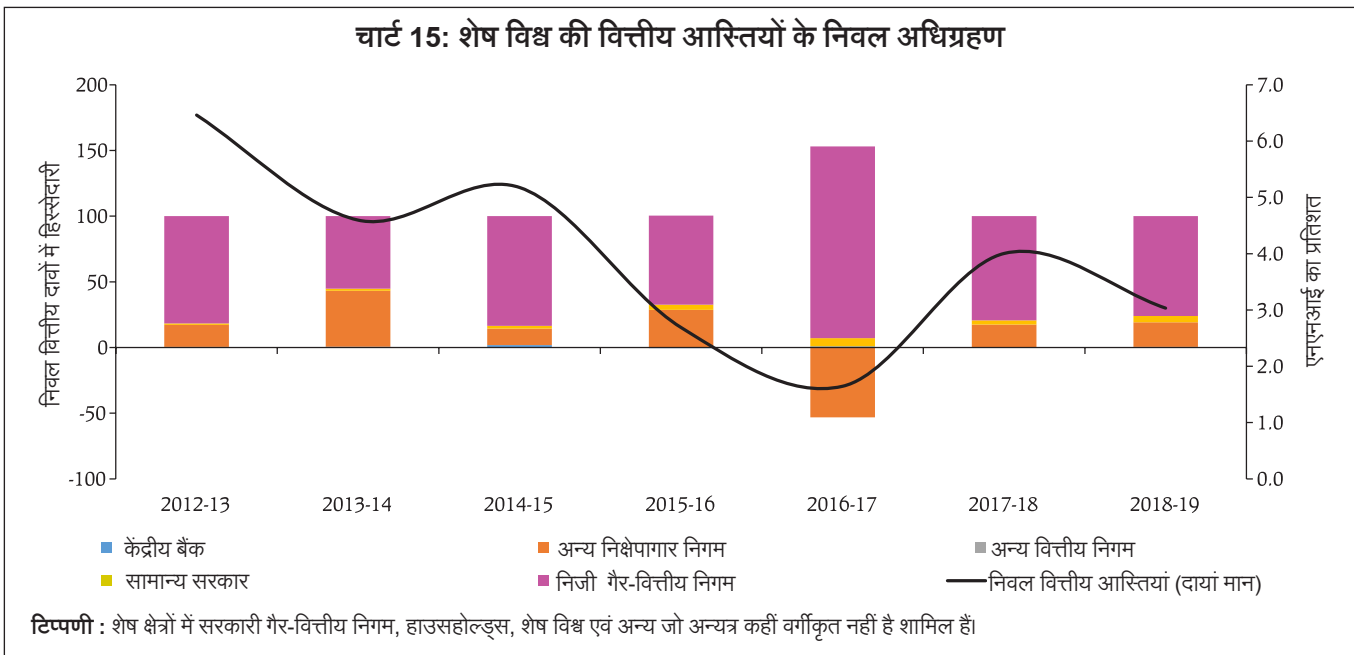
V. लिखतों के अनुसार वित्तीय प्रवाह

ऋण और उधार का कुल वित्तीय लेनदेनों में 29.0 प्रतिशत की सर्वाधिक हिस्सेदारी है, जिसके बाद 20.9 और 18.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ क्रमशः कर्ज प्रतिभूतियों व जमाराशियों का स्थान आता है। ऋण और उधार प्रमुख रूप से ओडीसी (67 प्रतिशत) द्वारा संवितरित किए गए हैं और हाउसहोल्ड्स एवं निजी एनएफसी के तुलन पत्र में प्रमुख रूप से देयता के रूप में धारित हैं।



वित्तीय लेनदेनों में लिखतों के उपयोग को लेकर कुछ फेरबदल देखे गए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान जमाराशियों की हिस्सेदारी में थोड़ा इजाफा होने के बावजूद उसमें गिरावट आई। लगभग 99 प्रतिशत जमाराशियां ओडीसी की देयताएं हैं, जिसमें से 62 प्रतिशत हाउसहोल्ड्स द्वारा धारण किए गए हैं। मुद्रा की हिस्सेदारी, जिसमें पुनर्मुद्राकरण की वजह से 2017-18 में सुधार हुआ, 2018-19 में घटी।

सामान्य सरकार और शेष विश्व द्वारा जारी की गई कर्ज प्रतिभूतियों – जो वित्तीय देयताओं में दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण लिखत है – में कटौती की वजह से उसमें 2018-19 के दौरान भारी गिरावट आई। कर्ज प्रतिभूतियां अधिकांशतः ओएफसी (42 प्रतिशत) द्वारा अभिदत्त हैं, जिसके बाद केंद्रीय बैंक और ओडीसी का स्थान आता है। इक्विटी के उपयोग ने वर्ष 2018-19 के दौरान जोर पकड़ा, जिसमें कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा शेयरों की



**सारणी 4: लिखतों के प्रकार के अनुसार वित्तीय प्रवाह
(कुल निर्गत दावों की प्रतिशत में हिस्सेदारी)**

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मुद्रा	2.6	1.9	2.6	4.1	-6.9	8.4	4.6
जमाराशियां	26.4	25.8	21.3	17.5	33.5	16.1	18.0
कर्ज प्रतिभूतियां	20.1	17.2	25.7	22.1	32.7	34.3	20.9
ऋण और उधार	31.1	21.7	17.7	23.3	7.0	20.9	29.0
इक्विटी	17.0	13.3	10.8	12.2	10.6	2.9	9.9
इन्वेस्टमेंट फंड शेयर / यूनिट्स	1.6	0.9	1.7	2.4	7.3	4.3	1.6
बीमा और सेवानिवृत्ति गारंटी योजनाएं	6.5	6.9	9.1	7.5	14.2	10.2	9.7
अन्य खाता प्राप्य / देय राशि	-5.4	12.4	10.8	10.7	0.9	2.1	5.8
अन्य मदें	0.1	0.0	0.3	0.3	0.8	0.9	0.5

वापसी खरीद की वजह से 2017-18 के दौरान कमी आई थी। वित्त बाजार में अस्थिरता के चलते म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी, जो साल भर बढ़ रही थी, में 2018-19 के दौरान गिरावट आई (सारणी 4)।

VI. निष्कर्ष

अर्थव्यवस्था का संपूर्ण वित्तीय संसाधन शेष, भले ही मामूली अधिशेष में है, 2018-19 के दौरान और भी खराब हुआ तथा 2019-20 के दौरान लंबी आर्थिक मंदी के चलते संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संसाधनों का अधिशेष और भी खराब होने की उम्मीद की जाती है। इसका तात्पर्य उच्च विदेशी वित्तीय प्रवाह होगा जबतक कि हाउसहोल्ड्स और गैर-वित्तीय निगमों के वित्तीय अधिशेष बेहतर होते हैं तथा सरकारी क्षेत्र के घाटे कम होते हैं।

अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि बहुत हद तक वित्तीय निगमों से होने वाले वित्तपोषण की ताकत पर निर्भर करेगी। घटते एनपीए की बदौलत 2018-19 में अन्य निक्षेपागार निगमों की वित्तीय निवल मालियत में थोड़ा सुधार हुआ। भविष्य में विनिर्माण क्षेत्र को बहाल करने और अर्थव्यवस्था में निजी निवेश में मदद करने के उद्देश्य से बैंकिंग क्षेत्र से होने वाले ऋण प्रवाह को बेहतर करने की जरूरत है। उसी समय, एनबीएफसी क्षेत्र की निरंतर मजबूती, सितंबर 2018 में आईएल और एफएस चूक के परिणामस्वरूप आए चलनिधि संकट के उपरांत, जोर पकड़नी चाहिए, जो वित्त जगत में नकदी विस्तार सुनिश्चित करेगी। वित्तीय निगम वित्तीय वातावरण को उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के लिए अधिक

अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और इस तरह निवेश को बढ़ावा देते हैं।

गैर-वित्तीय निगमों के मामले में, अधिक उधार लेने के चलते निजी और सरकारी संस्थाओं दोनों के संसाधनों की कमी 2018-19 में बढ़ी। वर्ष 2019-20 में, जहां पूंजी निर्माण में कमी के चलते निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र से उम्मीद की जाती है कि वे अपने संसाधनों की कमी को कम करेंगे, वहीं सरकारी क्षेत्र का घाटा बढ़ने की संभावना है। महामारी की शुरुआत से पहले भी एनएफसी के तुलन पत्र का बहुत अधिक फायदा उठाया गया है। कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए रियायती ऋण, अतिरिक्त ऋण सीमा, एवं कैपेक्स की बहाली तथा पर्याप्त नकदी-प्रवाह व लाभ करने के लिए कर में छूट समेत कुछ नीतियों का मेल कॉर्पोरेट क्षेत्र के तुलन पत्र में दबाव को कम करने में निर्णायक साबित हो सकता है। सरकारी गैर-वित्तीय निगमों के तुलन पत्रों की बहाली पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का घाटा प्रमुख रूप से कॉर्पोरेशन कर के तहत सकल राजस्व में गिरावट की वजह से और बढ़ने की उम्मीद है, जो कर की दरों में वर्ष के बीच हुई कटौती को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 में हाउसहोल्ड्स के निवल वित्तीय अधिशेष में गिरावट का शेष क्षेत्रों पर वित्त की उपलब्धता में कमी के संदर्भ में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। हाउसहोल्ड की बैंक जमाराशियों में वृद्धि और ऋणों एवं उधार में तेज गिरावट की वजह से 2019-20 में हाउसहोल्ड की वित्तीय बचत बेहतर होती प्रतीत होती है, जबकि बीमा और म्यूचुअल फंड में उनका निवेश गत वर्ष के समान स्तर पर रहा।

महामारी के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव से बहाली की राह पर लौटते हैं तो सभी क्षेत्रों में संसाधनों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण रहेगा। हाउसहोल्ड्स की ऐहतियातन बचत में वृद्धि की वजह से बैंक जमाराशियां बढ़ने की संभावना है, जबकि निवेश मांग कम होने के चलते ऋण लेने में कमी आने की संभावना है, नतीजतन अन्य निक्षेपागार निगमों के संसाधनों की कमी बढ़ जाती है। इसलिए, महामारी द्वारा बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में ऋण वितरण सुनिश्चित करने में वित्तीय बिचौलियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। 2020-21 में झांककर देखें तो, कोविड-19 महामारी से व्यवहार में बदलाव आने की उम्मीद की जाती है, जैसे, नकदी और कार्ड आधारित लेनदेनों की तुलना में इंटरनेट आधारित लेनदेन में बढ़ोत्तरी।

संदर्भ

- Aggarwal, D. K. (2017, February 24). "Buybacks hit six-year high in FY17; more companies are lining up offers", *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/buybacks-hit-six-year-high-in-fy17-more-companies-are-lining-up-offers/articleshow/57328786.cms?from=mdr>
- de Beer, B., Nhlapo, N., & Nhleko, Z. (2010). "A perspective on the South African flow of funds compilation—theory and analysis". *IFC Bulletin*, 33, 239-48.
- IMF and Financial Stability Board (2016), "The Financial Crisis and Information Gaps, Second Phase of the G20 DGI-2 First Progress Report".
- IMF and Financial Stability Board (2018), "The Financial Crisis and Information Gaps, Second Phase of the G20 DGI-2 Third Progress Report".
- IMF and Financial Stability Board (2019), "The Financial Crisis and Information Gaps, G20 DGI-2 The Fourth Progress Report—Countdown to 2021."
- Misra, Sangita, Samir Ranjan Behera, Kaushiki Singh and Saksham Sood (2020), "Provisional Accounts of Central Government Finances 2019-20: An Assessment", *RBI Bulletin*, June, 2020.
- OECD (2017), "Understanding Financial Accounts", Edited by Peter Van De Ven and Daniele Fano, OECD Publishing, Paris.
- Prakash, Anupam, Avdhesh Kumar Shukla, Anand Prakash Ekka and Kunal Priyadarshi (2018), "Quarterly Estimates of Households' Financial Assets and Liabilities", *RBI Bulletin*, March 2018.
- Prakash, Anupam, Avdhesh Kumar Shukla, Anand Prakash Ekka, Kunal Priyadarshi and Chaitali Bhowmick (2019), "Financial Stocks and Flows of the Indian Economy 2011-12 to 2017-18", *RBI Bulletin*, July 2019.
- Prakash, Anupam, Anand Prakash Ekka, Kunal Priyadarshi, Chaitali Bhowmick and Ishu Thakur (2020), "Quarterly Estimates of Households' Financial Assets and Liabilities", *RBI Bulletin*, June 2020.
- Government of India (2018), "Report of the Committee on Financial Sector Statistics", Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme and Implementation, Government of India.
- RBI (2019a), "Annual Report 2018-19", Reserve Bank of India.
- RBI (2019b), "Report on Trend and Progress of Banking in India 2018-19", Reserve Bank of India.
- RBI (2017), "Annual Report 2016-17", Reserve Bank of India.
- Sultana, Nasrin (2017, August 21), "Share buybacks poised to climb to a record ₹ 48,000 crore in 2017-18", *Livemint*. <https://www.livemint.com/Money/LAK14VcG9hi0Tsm5wUXUGO/Share-buybacks-poised-to-climb-to-a-record-Rs48000-crore-in.html>
- Singh, Kaushiki, Saksham Sood, Kirti Gupta and Neeraj Kumar (2019), "Union Budget 2019-20: An Assessment", *RBI Bulletin*, September, 2019.
- Tissot, B. (2016). "Development of financial sectoral accounts: New opportunities and challenges for supporting financial stability analysis"[Conference Paper]. 34th IARIW General Conference, Dresden, Germany.